



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2000/आषाढ़ 6, 1922

No. 136]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2000/ASADHA 6, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जून, 2000

फा. सं. 168/68/99-टी. सी.—सेवाओं पर कर लगाने के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए, सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. विशेषज्ञ दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | |
|--|----------|
| 1. डॉ. एम. गोविन्द राव,
निदेशक,
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | —अध्यक्ष |
| 2. श्री बी. सी. रस्तोगी,
भूतपूर्व अध्यक्ष
के. उ. शु. एवं सी. शु. बोर्ड | —सदस्य |
| 3. श्री डी. बी. लाल,
भूतपूर्व सदस्य
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | —सदस्य |
| 4. श्री अशोक वाधवा,
कर विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता | —सदस्य |
| 5. डा. अरविन्द विरमानी,
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,
वित्त मंत्रालय | —सदस्य |

6. प्रो. इन्दिरा राजा रमन, —सदस्य
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

श्री सुकुमार शंकर, सदस्य, के.उ.शु. एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विशेषज्ञ दल के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. विशेषज्ञ दल के लिए विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

- (i) सेवा कर के मौजूदा ढांचे की जांच करना और सेवाओं के क्षेत्र में कर आधार का विस्तार करने और लगने वाले समय के संबंध में सिफारिश करना।
- (ii) सेवा कर की वसूली की मौजूदा प्रक्रिया की जांच करना और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सिफारिशें करना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाना और अनुपालन लागत में कमी करना।
- (iii) उक्त मुद्दों से संबंधित अथवा उनसे प्रासंगिक किसी अन्य विषय पर सिफारिशें करना।

4. विशेषज्ञ दल, भारत सरकार की सहमति से अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकता है जिन्हें कराधान के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त हो, और/अथवा विशेषज्ञों को विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

5. विशेषज्ञ दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

6. राजस्व विभाग, या तो सीधे ही अथवा अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा विशेषज्ञ दल के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा।

7. विशेषज्ञ दल 31 अक्टूबर, 2000 तक वित्त मंत्रालय को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें ऐसी सिफारिशें दी गई होंगी जिन्हें वह तुरंत लागू करने के लिए आवश्यक समझता हो। विशेषज्ञ दल 31 दिसम्बर, 2000 तक वित्त मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर देगा।

टी. आर. रूस्तगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th June, 2000

F. No. 168/68/99-TC.—With a view to examining various aspects connected with the field of taxing the services and to make recommendations, the Government have decided to constitute an Expert Group.

2. The Expert Group will consist of the following:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dr. M. Govinda Rao,
Director,
Institute of Social & Economic Change | -Chairman |
| 2. Shri B.C. Rastogi,
Former Chairman,
Central Board of Excise & Customs | -Member |
| 3. Shri D.B. Lal,
Former Member,
Central Board of Direct Taxes | -Member |
| 4. Shri Ashok Wadhwa,
Tax Expert & Consultant | -Member |
| 5. Dr. Arvind Virmani,
Senior Economic Adviser,
Ministry of Finance | -Member |

6. Prof. Indira Raja Raman,
National Institute of Public Finance & Policy

-Member

Shri Sukumar Shankar, Member, Central Board of Excise & Customs, will work as Member Secretary of the Expert Group.

3. The terms of reference of the Expert Group will be :
 - (i) To examine the existing structure of service tax and to make recommendations on extending the tax base in the area of services, and the timing thereof.
 - (ii) To examine the existing procedure for collection of service tax, and to make recommendations as may be considered necessary for making it more effective, to augment voluntary compliance, and to reduce compliance cost.
 - (iii) To make recommendations on any other matter related to the above points or incidental thereto.
4. The Expert Group may co-opt, with the concurrence of the Government of India, other members who have experience and expertise in the area of taxation, and/or invite experts for discussions.
5. The Headquarters of the Expert Group will be at New Delhi.
6. The Department of Revenue will provide the Secretariat for the Expert Group either directly or through any of its subordinate offices.
7. The Expert Group will submit an interim report to the Finance Ministry by 31st October, 2000, containing such recommendation as it considers important for immediate implementation. The Expert Group will submit the final report to the Finance Ministry by 31st December, 2000.

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

